



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 05 जुलाई, 2018 / 14 आषाढ़, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-118/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

### अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	18/1993	बनोला	पनेहल	19/1, 38/1, 549/1, 550/1, 589/1 किता.. 5	7-35-75	उत्तर: बड़ाच दक्षिण: पनेहल पूर्व: पनेहल पश्चिम: पनेहल	ननखड़ी	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा,  
तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-118/2014, dated 11<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> June, 2018*

**No. FFE-B-F(14)-118/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section(3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	18/1993	Banola	Panehal	19/1, 38/1, 549/1, 550/1, 589/1 Kitta..5	7-35-75	North: Badach South: Panehal East: Panehal West: Panehal	Nan-khari	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,

Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 11 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-121/2014.—** इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल/ उप महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	53/1993	बनोगा	पनेहल	1729/1, 2062, 2063/1 किता.. 3	39-57-05	उत्तर: पनेहल दक्षिण: कलयोग पूर्व: लैलन व डीपीएफ थैली पश्चिम: पनेहल	ननखड़ी	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा,

तरुण कपूर,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-121/2014, dated 11<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11<sup>th</sup> June, 2018*

**No. FFE-B-F(14)-121/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section(3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	53/1993	Banoga	Panehal	1729/1, 2062, 2063/1 Kitta-3	39-57-05	North: Panehal  South: Kalyog  East: Lellan and DPF Thaili  West: Panehal	Nan - Khari	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,  
*Additional Chief Secretary (Forests).*

## वन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-122/2014.—** इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	57 / 1993	बलानी	पनेहल	723 / 1, 801 / 1, 821 / 1, 847 / 1, 949 / 1, 1337 / 1, 1338, 1339 / 1, 1415, 1416, 1419 / 1  किता.. 13	800 / 1, 822 / 1,	9—15—44  उत्तर: पनेहल  दक्षिण: पनेहल  पूर्व: पनेहल  पश्चिम: पनेहल	ननखड़ी	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा,

तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-122/2014 dated 11<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> June, 2018

**No. FFE-B-F(14)-122/2014.—**Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section(3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

#### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	57/1993	Balani	Panehal	723/1, 800/1, 801/1, 821/1, 822/1, 847/1, 949/1, 1337/1, 1338, 1339/1, 1415, 1416, 1419/1 Kitta. .13	9-15-44	North: Panehal South: Panehal East: Panehal West: Panehal	Nan - Khari	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

#### वन विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-124/2014.**— इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	30/1994	नागाधार	नागाधार	678/1, 679/1, 843/1, 864/1 किता.. 4	37-63-48	उत्तर: टूटू दक्षिण: नागाधार पूर्व: पनेहल पश्चिम: नागाधार	ननखडी	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा

तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-----

[Authoritative English text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-124/2014, dated 11<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> June, 2018

**No. FFE-B-F(14)-124/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of sub-section (2) of Section-29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1.	30/1994	Nagadhar	Naga-dhar	678/1, 679/1, 843/1, 864/1  Kitta-4	37-63-48	North: Tutu  South: Nagadhar  East: Panehal  West: Nagadhar	Nan-Khari	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 11 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-131/2014.**— इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।



## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	20/1993	चेवड़ी	चेवड़ी	701/1, 793, 794/1 किता.. 3	67-32-08	उत्तर: दनेवटी दक्षिण: लाडू पूर्व: चेवड़ी पश्चिम: जूणी	ननखडी	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा,

तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-131/2014 dated 11<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> June, 2018

**No.FFE-B-F(14)-131/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	20/1993	Chevadi	Chevadi	701/1, 793, 794/1  Kitta-3	67-32-08	North- Danevati  South: Ladu  East: Chevadi  West: Juni	Nan- Khari	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 11 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ (14)-137/2014.**— इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल/उप महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	24/1994	पड़धार,	कुन्गल	2, 50/1, 54/1, 105/1, 214/1, 695 किता .. 6	23-32-56	उत्तर: धरागला दक्षिण: मुन्दर पूर्व: खौड़ी पश्चिम: गड़ासू	ननखड़ी	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा,

तरुण कपूर  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-137/2014 dated 11<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 11<sup>th</sup> June, 2018

**No. FFE-B-F(14)-137/2014.**—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of Sub-Section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

## SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ UpMuhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	24/1994	Paddhar	Kungal	2, 50/1, 54/1, 105/1, 214/1, 695  Kitta.. 6	23-32-56	North: Dhragla  South: Mundar  East: Khouidi  West: Gadasu	Nan - khari	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जून, 2018

**संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ(14)-96/2014.**—इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि/बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि/बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतदपश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी ।

## अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	61/1993	सुरड	सुरड	1107/1, 1111/1, 1243/1, 1244/1 किता.. 4	13-10-34	उत्तर: सुरड दक्षिण: सुरड पूर्व: सुरड पश्चिम: सुरड	बाहली	रामपुर	शिमला

आदेश द्वारा,

तरुण कपूर,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-96/2014, dated 8<sup>th</sup> June, 2018 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 8<sup>th</sup> June, 2018

**No.FFE-B-F(14)-96/2014.**— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/Waste Land and shall hereafter be called as “Protected Forests” under the provisions of sub section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	61/1993	Surad	Surad	1107/1, 1111/1, 1243/1, 1244/1  Kitta.. 4	13-10-34	North: Surad  South: Surad  East: Surad  West: Surad	Bahali	Rampur	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**नगर एवं ग्राम योजना विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 3 जुलाई, 2018

**संख्या: टीसीपी-ए(3)-1/2016-1.**—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 के प्रारूप को, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, तद्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25-04-2018 द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी.सी.पी.ए (3)-1/2014-1 तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 है।

**2. नियम 16 का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है, के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“(1) अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) धारा 30-क या (धारा 30-क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक) या धारा 78 त के अधीन किसी भूमि के विकास को कार्यान्वित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसे विकास हेतु आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न विनिर्देश और क्षेत्र की अनुसूची के साथ प्ररूप-11 में भूमि के उप-खण्ड (सब डिविजन) हेतु और प्ररूप 12 में भवन के सन्निर्माण हेतु या तो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30 क (धारा 30 क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक) या धारा 78 त के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न यथाविनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी:—

क्र०सं०	संघटक	निर्मित क्षेत्र के प्रति वर्ग-मीटर की इकाई	नगरपालिका सीमाओं में		नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से बाहर अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र	
			आवासीय उपयोग	आवासीय उपयोग से भिन्न ₹	आवासीय उपयोग ₹	आवासीय उपयोग से भिन्न ₹
1.	भवन निर्माण योजना की अनुज्ञा/मंजूरी/संशोधन के लिए फीस	वर्गमीटर	8.00	10.00	5.00	8.00
2.	परिवर्धन/परिवर्तन/पुनर्विधिमन्यता के लिए फीस।	वर्गमीटर	8.00	10.00	5.00	8.00
3.	भूमि के उप-खण्ड (सब डिविजन) के अनुमोदन के लिए फीस।	वर्गमीटर	2.50		1.00	
4.	अन्तरिम विकास योजना/विकास योजना में यथाविहित उपयोग से प्रस्तावित भूमि उपयोग में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए फीस।	वर्गमीटर	16.00	20.00	10.00	16.00

**टिप्पण.—**(i) शहरी स्थानीय निकायों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को उपरोक्त संघटकों के अधीन संशोधित एकात्मक फीस उद्ग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) के परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक आवास स्कीमों के 100 वर्गमीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के आवेदकों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। यह प्रसुविधा किसी परिवार द्वारा केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी। तथापि, यदि प्लॉट क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक का है तो अतिरिक्त क्षेत्र पर फीस प्रभारित की जाएगी।”।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना,  
प्रधान सचिव (टी०सी०पी०)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-A (3)-1/2016-I Dated 03-07-2018 as Required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, 3rd July, 2018*

**No. TCP-A(3)-1/2016-1.**—Whereas, the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Third Amendment) Rules, 2018 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, *vide* this Department's Notification of even number dated 25-04-2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub-section (I) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977);

And whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified *vide* this Department Notification No. TCP-A(3)-1/2014-I dated 1-12-2014 published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1-12-2014, namely:—

**1. Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Third Amendment) Rules, 2018.

**2. Substitution of rule 16.**—For rule 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the following rule shall be substituted, namely:—

“(1) Any person, intending to carry out development of any land under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) or section 78p of the Act may apply for such development in Form-11 for sub-division of land and Form-12 for construction of building alongwith the Specification and Schedule of area attached with the application form either personally or online.

(2) Every application submitted under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) or section 78 p of the Act shall be accompanied by fee as specified below:—

Sl. No.	Component	Unit Per Square Metre of built up area	Municipal Limits		Outside Municipal Limits <i>i.e.</i> Rural Area	
			Residential Use ₹	Other than Residential Use ₹	Residential Use ₹	Other than Residential Use ₹
1.	Fee for building permission/sanction/revision of building plan.	M <sup>2</sup>	8.00	10.00	5.00	8.00



2.	Fee for addition/alteration/revalidation.	M <sup>2</sup>	8.00	10.00	5.00	8.00
3.	Fee for approval of Sub-division of land.	M <sup>2</sup>	2.50		1.00	
4.	Fee for Change of Land Use from the use as prescribed in the Interim Development Plan/ Development Plan to propose land use.	M <sup>2</sup>	16.00	20.00	10.00	16.00

**Note.**— (i) The Urban Local Bodies and Special Area Development Authorities shall have the liberty to levy amended unitary fee under above components.

(ii) No fee shall be charged from the Below Poverty Line (BPL) families, Economically Weaker Sections (EWS) of the society and from the applicants of Social Housing Schemes notified by the Government from time to time upto 100 M<sup>2</sup> plot area. This benefit may be availed by a family only once. However, if the plot area is above 100M<sup>2</sup>, the fee shall be charged on the additional area”.

By order,  
PRABODH SAXENA,  
Principal Secretary (TCP).

कार्मिक विभाग  
(सचिवालय प्रशासन सेवायें-I)

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जून, 2018

**संख्या: पीईआर-(एसएस-I) बी (2)-5/2017.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या कार्मिक (सचिवालय प्रशासन-I) ए(3)-1/85-I तारीख 26-08-2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 29-10-2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) में **फ्राश एवं चौकीदार एवं माली** (वर्ग-IV अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) फ्राश एवं चौकीदार एवं माली वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) फ्राश एवं चौकीदार एवं माली (वर्ग-IV अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2014 के उपाबन्ध 'क' में,—

(क) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। ” ;

(ख) स्तम्भ संख्या 15क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“संविदा नियुक्त की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन विहित शैक्षिक अर्हता के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। ” ; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15क (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा। ”।

**3. उपाबन्ध 'ख' का संशोधन.**—इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' में क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा। ”।

**4. परिशिष्ट-I का जोड़ा जाना.**—उक्त नियमों में 'निम्न परिशिष्ट-I' जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

1.	लिखित परीक्षा	
	{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है :-  (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षित अर्हता हेतु अधिमान । =2.5 अंक  {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ( $50 \times 0.025 = 1.25$ ) अनुज्ञात किए जाएंगे}।  (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित । =01 अंक  (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा =01 अंक  (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है =01 अंक  (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन =01 अंक  (vi) एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष)/एन0सी0सी0 में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता =01 अंक  (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित ₹40,000/- से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब =02 अंक  (viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला =01 अंक  (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ =01 अंक  (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण =01 अंक  (xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक	15 अंक

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / —  
सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (SAS-I) A (3)-1/85-I dated ..... required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

**PERSONNEL DEPARTMENT**  
**(Secretariat Administration Services-I)**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 25<sup>th</sup> June, 2018*

**No. Per (SAS-I) B (2)-5/2017.**— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration) **Frash cum-Chowkidar-cum-Mali** (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2014 notified *vide* this Department's Notification No. Per (SAS) A(3)-1/85-I, dated 26-08-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 29-10-2014 namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration) *Frash-cum-Chowkidar-cum-Mali* (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment & Promotion (First Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure "A".**—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) *Frash cum Chowkidar cum Mali* (Class-IV, Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2014,—

- (a) for the existing provisions against Column No.15, the following shall be substituted, namely:—

“Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules.” ;

- (b) for the existing provisions against Column No. 15 A(IV), the following shall be substituted namely:—

“Selection for appointment to the post in the case of contract recruitment shall be made on the basis of merit of prescribed educational qualification followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules” ;

- (c) for the existing provisions against Column No.15 A(VII) (C), the following shall be substituted namely:—

“The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical

Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.”

**3. Amendment of Annexure-B.**—In Annexure “B” appended to the said rules for the provisions against Sl. No.4, the following shall be substituted, namely:—

“The contract appointee will be entitled for one day’s casual leave after putting one month’s service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.”.

**4. Addition of Appendix-1.**—After the said rules, the following Appendix-I shall be inserted, namely:—

“APPENDIX-I  
FOR CLASS-IV POST

1.	Merit of minimum educational qualification, in terms of the Recruitment & Promotion Rules, shall be calculated as under:—  {Percentage of marks obtained in prescribed educational qualification to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks}.	85 Marks
2.	Evaluation of candidates to be made in the following manner):—  (i) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be =01 Mark  (ii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =02 Marks  (iii) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service =2.5 Marks  (iv) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity =01 Mark	15 Marks

(v)	NSS (at least one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions 01 Marks	
(vi)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time =2.5 Marks	
(vii)	Widow/divorced/destitute/single woman =1.5 Marks	
(viii)	Single daughter / Orphan =01 Mark	
(ix)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks.”	

By order,  
Sd/-  
Secretary (SA).

## FINANCE (PENSION) DEPARTMENT

### OFFICE MEMORANDUM

Shimla-171002, the 4<sup>th</sup> July, 2018

**Subject:— Restoration of full pension in respect of Govt. servants who had drawn lump-sum amount in lieu of pension on absorption in Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies.**

**No. Fin (Pen) B (10)-3/2018.**—In partial modification of OM No. Fin (Pen) A (3)2/88 dated 11-2-1991, the State Government *vide* OM No. Fin(Pen)A(3)-2/88 dated 8th January, 1997 had decided that the benefit of restoration of 1/3rd commuted portion of pension after 15 years from the date of such commutation shall also be admissible to all those Govt. employees who had been absorbed in Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies/Statutory Bodies etc., notwithstanding the fact that having commuted the full pension, they were not in receipt of any monthly pension.

2. Thereafter, instructions to revise restored amount of 1/3rd commuted portion of pension in respect of Govt. servants who had drawn lump-sum amount on their permanent absorption in Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies *w.e.f.* 1-1-1986 and 1-1-1996 were issued *vide* Govt. OM No. Fin (Pen)A(3)-1/97-I, dated 4th June, 2005 and Office Memoranda of even number dated 3rd April, 2008 and dated 21st August, 2008 respectively. Further, instructions to revise the restored 1/3<sup>rd</sup> commuted portion of pension *w.e.f.* 1-1-2006 were issued *vide* office Memorandum No. Fin (Pen) A (3)-1/09-Part-III, dated 14-10-2009.

3. In order to give relief to such absorbee pensioners, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Government servants who had drawn 100% lump-sum amount in lieu of pension (1/3rd as well as 2/3rd) on their absorption in Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies and in whose case 1/3rd pension has been restored, may be allowed restoration of full pension as per details in para-4 below.

4. The benefit of restoration of full pension shall be allowed from the prospective date *i.e.* from the date of publication of these instructions **or** completion of 20 years from the date of payment of 100% lump-sum amount, whichever is later.

5. All the concerned H.P. Government absorbees in Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies etc. shall apply to the respective Administrative Department/Office from where they had retired, for restoration of the full pension and the concerned Administrative Department/Office shall, after verification of claims from the relevant records, forward the papers to the Accountant General (A&E) Himachal Pradesh for authorization and to revise the Pension Payment Orders (PPOs) accordingly.

6. This order shall take effect from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,  
Sd/-  
*Addl. Chief Secretary (Finance).*

To

**All Administrative Departments  
Government of Himachal Pradesh.**

---

**Visit Finance Department – [www.himachal .gov.in/finance/](http://www.himachal.gov.in/finance/)**

**Endst. No. Fin (Pen) B (10)-3/2018**

**Dated: 04/07 / 2018**

1. The Divisional Commissioner Shimla, Mandi and Kangra at Dharamshala, Himachal Pradesh.
2. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
3. The Resident Commissioner, Himachal Pradesh, Himachal Bhawan, 27-Sikandra Road, New Delhi-110001 with 10 spare copies.
4. The Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, Shimla-171003 with 10 spare copies.
5. The Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Shimla-171003 with 10 spare copies for circulation to all the Accountant General in India with special stamp.
6. The Director, H.P. Institute of Public Administration, Mashobra, Shimla-171012.
7. The Registrar, H.P. High Court, Shimla-171001.
8. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
9. All District and Sessions Judges in Himachal Pradesh.
10. All District Treasury Officers/Treasury Officers in H.P. with 10 spare copies.

11. All Joint Controllers/Deputy Controllers (F&A)/Asstt. Controllers (F&A)/Section Officers (F&A) under the Control of Treasury & Accounts Organization.
12. The Pay & Accounts Officer, No. 6, Reserve Bank of India, Sansad Marg, New Delhi-110001.
13. The Deputy Commissioner (Relief & Rehabilitation), Raja Ka Talab, Nurpur-176051 (Kangra).
14. The Chief General Manager, Reserve Bank of India, C-7, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 with 10 spare copies for necessary action.
15. The Executive Director, Reserve Bank of India, Central Office Building, 17th Floor, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai-400001.
16. The Managing Director, State Bank of Patiala, The Mall, Patiala, Punjab-147001.
17. The General Manager, UCO Bank, Head office-10, Binlahi Trelocav Maharaj Sarani, Kolkata -700001(West Bengal).
18. The General Manager, Union Bank of India, Union Bhavan-239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021 (Maharashtra).
19. The General Manager, Punjab National Bank, Head Office-5, Sansad Marg New Delhi-110001.
20. The General Manager, Central Bank of India, Chandramukhi 16th Floor Nariman Point, Mumbai-400021.
21. The Deputy General Manager, State Bank of India, Zonal Office, SDA-Complex Kasumpti, Shimla-171009 with 10 spare copies.
22. The Chief Manager, Central Bank of India, Central Bank Building, Sector-17-B, Chandigarh-160017 with 10 spare copies for circulation amongst the Branches of the Bank situated in Himachal Pradesh.
23. The Deputy General Manager, Union Bank of India, 64/65 Bank Square, Sector-17-B, Chandigarh-160017 with 10 spare copies for circulation amongst the Branches of the Bank situated in Himachal Pradesh and other States.
24. The Regional Manager, UCO Bank, Zonal Office, Himland Hotel, Shimla-1 with 10 spare copies.
25. The Regional Manager, UCO Bank, Regional Office, Shyamnagar, Dharamshala-176215 (H.P.) with 10 spare copies.
26. The Regional Manager, Central Bank of India, Timber House, Shimla-171001 with 10 spare copies.
27. The Regional Manager, Punjab National Bank, The Mall, Shimla-171001 (Regional Office) with 10 spare copies.
28. The Regional Manager, Punjab National Bank, 287, Civil Lines, Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.-176215 with 10 spare copies.



29. The Regional Manager, Punjab National Bank, Circle Officer Jail Road Mandi, H.P.-175001 with 10 spare copies for circulation amongst the Branches of the Bank situated in Himachal Pradesh.
30. The Zonal Manager, Punjab National Bank, PNB House (Bank square), Sector-17, Chandigarh-160017 with 10 spare copies.
31. The General Manager, Bank of India, Star House C-5, G Block, 7th Floor Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051.
32. The Zonal Manager, SCO-181-182, Bank of India, Chandigarh Zone, Sector-17-C, Post Box No.6, Chandigarh-160017.
33. The Senior Branch Manager, Bank of India, 45, The Mall Shimla-171001 with 10 spare copies.
34. The Chief Manager, State Bank of India, Greater Kailash-I (Zamroodpur), New Delhi-110048.
35. The General Manager, State Bank of India, Chandni Chowk Main Branch, New Delhi-110006.
36. The Manager, State Bank of India, Nirman Bhawan, Branch Malauna Azad Road, New Delhi-110011.
37. The Manager, UCO Bank, 35 Ferozashah Road, ICSSR building near Mandi House Crossing, New Delhi-110002.
38. The Manager, State Bank of India (Pension Cell), Govindpura, Bhopal (M.P.)-462021.
39. The Manager, State Bank of India, Sector-35C, Chandigarh.
40. The Manager, Bank of Baroda, CPPC, Head Office, 7<sup>th</sup> Floor, Suraj Plaza-I, Sayajigunj, Baroda, Vadodara, Gujarat-390005.
41. The Asstt. General Manager, State Bank of India, Centralised Pension Processing Centre, Chandigarh, Sector-5, Panchkula-134101 (Haryana).
42. The Manager, Corporation Bank, Bhikaji Kama Palace, New Delhi-110066.
43. The Under Secretary (Finance Commission), H.P. Sectt. Shimla-171002.
44. All Sections of Finance Department, H.P. Sectt. Shimla- 171002.
45. The Controller (F&A) Personnel Accounts Department, H.P. Sectt. Shimla-2.
46. The Deputy Chief Officer (Accounts), Regional Office, UCO Bank, Sansad Marg, New Delhi-110001.

47. Incharge, NIC, H.P. Sectt. Shimla-2 with the request that this order of the State Government may kindly be uploaded on State Finance Department Website so that the Pensioners/Family Pensioners living outside the State may get the benefit of this order well in time.

By order,  
Sd/-  
*Secretary (Finance).*

**Endst. No. Fin (Pen) B (10)-3/2018**

**Dated: 04 /07/ 2018**

**Copy forwarded to:—**

1. The Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Hyderabad with 10 spare copies.
2. The Accountant General (A&E), Assam, Guwahati with 10 spare copies.
3. The Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima with 10 spare copies.
4. The Accountant General (A&E), Tripura, Agartala with 10 spare copies.
5. The Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong with 10 spare copies.
6. The Accountant General (A&E), Manipur, Imphal with 10 spare copies.
7. The Accountant General (A&E), Bihar, Patna with 10 spare copies.
8. The Accountant General (A&E), Maharashtra, Mumbai with 10 spare copies.
9. The Chief Accountant General (A&E), West Bengal, Kolkata with 10 spare copies.
10. The Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad with 10 spare copies.
11. The Accountant General (A&E), J&K Srinagar with 10 spare copies.
12. The Accountant General (A&E), Karnatka, Bangalore with 10 spare copies.
13. The Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram with 10 spare copies.
14. The Principal Accountant General A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002 with 10 spare copies.
15. The Accountant General (A&E), Chhattisgarh at Raipur with 10 spare copies.
16. The Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubneswar with 10 spare copies.
17. The Accountant General (A&E), Punjab, Chandigarh with 10 spare copies.
18. The Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur with 10 spare copies.

19. The Accountant General (A&E), Tamilnadu, Chennai with 10 spare copies.
20. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh with 10 spare copies.
21. The Accountant General (A&E) Uttar Pradesh, Allahbad with 10 spare copies.
22. The Accountant General (A&E), Sikkim, Gangtok with 10 spare copies.
23. The Accountant General (A&E) Jharkhand at Ranchi with 10 spare copies.
24. The Principal Accountant General (A&E) II, Uttarakhand, Oberai Motors Building, Saharanpur Road, Majra Dehradun with 10 spare copies.
25. The Controller of Accounts, Principal Accounts Office, Vikas Bhawan, A-Block, New Delhi with 10 spare copies.
26. The Pay & Accounts Officer, No.-5, Tis Hazari, New Delhi-110054 with 10 spare copies.

By order,  
Sd/-  
*Secretary (Finance).*

